विचार बिन्दु

अपनी नम्रता का गर्व करने से अधिक निंदनीय और कुछ नहीं है। –मारकस

गरीबी पर चिंता बहुत, मगर बढ़ रही अमीरों की अमीरी

आजादी के बाद से ही हमारे नेता गरीबों की हमेशा चिंता की बातें ही नहीं करते रहे हैं, बल्कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने के दावे लेकर भी सामने आते रहे हैं। एक समय गरीबी हटाओ बड़ा नारा हुआ करता था जिस पर भरोसा करके अवाम नेताओं को सत्ता में बिठाया करती थी। कभी समाजवाद के जरिए गरीब की हालत सुधार कर उसके और अमीर के बीच की सीमा रेखा मिटाने के जतन किये गये, तो कभी खुली आर्थिक नीतियों से सबकी झोलियां भरने के उद्यम किए गये। लेकिन हर बार घूम-फिर कर यही बात सामने आई कि अमीरों की अमीरी और गरीबों की संख्या बढ़ रही है। अब तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सार्वजनिक रूप से गरीबों की 'बढ़ती' संख्या पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि "धीरे-धीरे गरीबों की संख्या बढ़ रही है और धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से बढ़ना चाहिए कि रोजगार पैदा हो और ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि "हम एक ऐसे आर्थिक विकल्प पर विचार कर रहे हैं जो रोजगार पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देगा।"

जब कोई केन्द्रीय मंत्री ऐसे आर्थिक विकल्प की बात करता है जिसमें वैसी अर्थव्यवस्था बनाना हो जो रोजगार पैदा करे तब सवाल उठता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था कैसी होगी और वे क्या बाधाएं हैं जो ऐसा नहीं होने देती? हर बार हम इसी पेच में फंस जाते हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो रोजगार बढ़ेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था छलांग लगा कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है फिर भी प्रधान मंत्री को अपने भाषणों में देश की 80 प्रतिशत आबादी को गरीब बताना पड़ता है। इससे यह समझ में आ जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था बढ़ने से गरीबी नहीं मिटती बल्कि अमीरों की अमीरी बढ़ती है। अब समय आ गया है कि इससे उलटा सोचा जाए। रोजगार बढ़ेंगे तब ही देश की अर्थव्यवस्था के साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। इसके लिये जरूरी है कि देश के गरीब लोगों के हाथों में रोजगार पाने का हुनर दिया जाय ताकि वे देश की अर्थ व्यवस्था में उत्पादक रूप से शामिल हो सकें। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी घट कर 14 प्रतिशत रह गई है, मगर उस पर अब भी 48 प्रतिशत आबादी निर्भर करती है। यह अवहनीय स्थिति है। इस ग्रामीण आबादी को अन्य उत्पादक क्षेत्रों में शिफ्ट करना ही एक रास्ता है। यह तभी हो सकता है जब उनको गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा तथा काम-काज के हुनर की दक्षता का प्रशिक्षण मिले। अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था भेद करती है। अमीर अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर लेता है, मगर गरीब ऐसा नहीं कर पाता है और उसके बच्चे फिसड्डी रह जाते हैं। ऐसे में क्या किया जाय? इसके लिए जाने-माने जनसंख्याविद् डॉ. देवेन्द्र कोठारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मानव संसाधन विकास का एक उत्तम मॉडल बना कर दे चुके हैं। यह मॉडल, जो अपने लिए बजट में किसी अलग प्रावधान की मांग नहीं करता, को देश-दुनिया के अकादमिक क्षेत्रों में तो खूब सराहना मिली किन्तु हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को उसे देखने समझने की फुरसत नहीं मिली।

वैश्विक अनुभव से भी पता चलता है कि सामाजिक कल्याण के पहलुओं पर अधिक ध्यान देने वाले देश मानव संसाधनों की गुणवत्ता को बढ़ा कर सफलतापूर्वक अपनी आय या विकास के स्तर को अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ा सकते हैं। यह भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। भले ही विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे नेताओं द्वारा ज्ञान-अर्थव्यवस्था (नॉलेज इकॉनोमी) के निर्माण की बातें बढ़-चढ़ कर की जाती रही हैं, किन्तु मानव संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करने में देश पीछे रह गया है। निश्चित रूप से यह स्पष्ट है कि मानव विकास को बेहतर बनाने के लिए अधिक संसाधनों के आवंटन के साथ काम-काज में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि भारत के मानव विकास के प्रयास पिछले दशकों में किए गए शुरुआती लाभ के बाद लड़खड़ा गए हैं। हालांकि समग्र रुझान अब भी दिखाते हैं कि 1990-2022 में भारत के मानव संसाधन सूचकांक (एचडीआई) में 1.24 प्रतिशत वार्षिक औसत सुधार हुआ जो वैश्विक सुधार की गति से दोगुना अधिक होने के करीब रहा है, किन्तु बाद में यह अंतर कम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत की एचडीआई वृद्धि दर, जो पहले 1990-2000 में 1.22 प्रतिशत से बढ़कर 2000 और 2010 के बीच 1.56 प्रतिशत हो गई थी, अब 2010-22 की अवधि में लगभग एक तिहाई घटकर केवल 0.99 प्रतिशत रह गई। वैश्विक मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) रैंकिंग में भारत का स्थान 2022 में एक पायदान बढ़कर 134वें स्थान पर पहुंच गया, जो उसके पिछले वर्ष से एक पायदान ऊपर था। भारत मानव विकास की मध्यम श्रेणी में है और हाल के वर्षों में दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। वर्ष 2015 और 2022 के बीच भारत की रैंक केवल चार पायदान ऊपर बढ़ी है। अन्य देशों को देखते हुए यह एक बड़ी गिरावट है इस अवधि के दौरान अन्य देशों ने अधिक प्रभावशाली लाभ दर्ज किए है। परेशान करने वाली बात यह है कि भारत की एचडीआई रैंकिंग इसकी वैश्विक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) रैंकिंग से छह पायदान नीचे है, जो इसके विकास के अनुमानित स्तर को दर्शाती है। यह उन देशों की बढ़ती संख्या के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने सामाजिक कल्याण के लाभों को बढ़ावा देकर अपनी आय या विकास रैंकिंग की तुलना में उच्चतर मानव विकास रैंकिंग में बढ़ोतरी सुनिश्चित की है।

> **जाने-माने जनसंख्याविद् डॉ. देवेन्द्र कोठारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मानव संसाधन विकास का एक उत्तम मॉडल बना कर दे चुके हैं। यह मॉडल, जो अपने लिए बजट में किसी अलग प्रावधान की मांग नहीं करता, को देश-दुनिया के अकादमिक क्षेत्रों में तो खूब सराहना मिली किन्तु हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को उसे देखने-समझने की फुरसत नहीं मिली।**

मानव संसाधन विकास के लिए भारत की कमजोर तैयारी और प्रदर्शन स्कूली शिक्षा में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रति वर्ष जारी होने वाली 'असर' की रिपोर्टें बार-बार बताती आई हैं कि सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई की हालत सोचनीय है। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में केवल अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चे ही पढ़ने आते हैं। हमें नहीं मालूम गडकरी साहब जिस वैकल्पित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं वह क्या है लेकिन डॉ. कोठारी कहा करते थे कि सरकार को अमीरों की पढ़ाई का काम उनकी निजी व्यवस्था पर छोड़ कर अपना पूरा ध्यान केवल गरीब की शिक्षा पर लगाना चाहिए। अमीर अपना हाल संभाल लेंगे और सरकार को अपने संसाधन व ऊर्जा गरीबों के बच्चों की शिक्षा पर लगानी चाहिए। इन प्रयासों में स्कूली शिक्षा का ढांचा सुधारने तथा वहां गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना तो है ही, किन्तु साथ ही गरीब बच्चों के स्वास्थ्य की भी जिम्मेवारी लेनी होगी। बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो स्कूल नियमित किस प्रकार आएगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। यह केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने आने वाले बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल कर देने भर से नहीं होगा। उनके परिवारों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य के उपाय करने होंगे। उसके लिए उनके परिवारों की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। तभी गरीब बच्चे स्वस्थ रह कर स्कूलों में रुचिकर माहौल में अपनी पढ़ाई बरकरार रख सकेंगे। ऐसे गरीब परिवारों का नया डाटा बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ सरकारी स्कूलों को ले लीजिए। उनमें नामांकित बच्चों का डाटा तैयार पड़ा है। बस उनके परिवारों तक पहुंचना है। उन परिवारों को जो मदद करनी है उसकी योजनाएं पहले से ही चल रही है। उन योजनाओं को सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों के परिवारों पर केंद्रित करनी है। किसी भी अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत होगी तो वे उच्च शिक्षा में भी बेहतर कर पाएंगे और अमीर बच्चों की प्रतिस्पर्धा में आ सकेंगे। वे उच्च शिक्षा में न जाकर भी हुनर के प्रशिक्षण लेकर उत्पादक कामों में लग कर देश की अर्थ व्यवस्था में खुद को शामिल कर पाएंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था उत्पादकता उन्मुख होगी जिसमें सबकी समान भागीदारी होगी। इससे वैसा समता वाला समाज बन सकेगा जिसकी भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है। भारत के सबसे गरीब 40 प्रतिशत के पास जहां कुल आय का केवल 20 प्रतिशत है, वहीं सबसे अमीर एक प्रतिशत के पास 21.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। यह विकास के लिए एक बड़ी बाधा है क्योंकि अध्ययनों से पता चलता है कि आय के अत्यधिक केन्द्रीकरण से गरीब सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। डॉ. कोठारी का एचडी प्लस मॉडल हो या कोई और हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति संविधान निर्देशित राज्य की जिम्मेवारी निभे बिना कुछ नहीं हो सकता। खुली अर्थ व्यवस्था में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का जबरदस्त निजीकरण हुआ है। दोनों क्षेत्रों में निजी सेवाएं मुनाफा कमाने के लिए सुरसा की तरह मुंह फाड़ती सबको दिख रही है। यह निजीकरण सार्वजनिक सेवाओं की कीमत पर हो रहा है। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर गरीब तो सार्वजनिक सेवाओं पर ही निर्भर है और वह वहां अपने को पिटा हुआ, ठगा हुआ महसूस करता है। अर्थव्यवस्था में सबकी भागीदारी के लिए यदि राज्य आज काम शुरू करता है तो उसके परिणाम आने में कम से कम दस वर्ष लगेंगे जब गरीब बच्चे गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा पूरी कर हुनर के प्रशिक्षण के लिए तैयार होंगे। गडकरी साहब ने जिस वैकल्पिक मॉडल की बात की है उसमें इन चुनौतियों का सामना करने की व्यवस्था है, हमें नहीं मालूम।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

सफलता की कहानी-चित्तौड़गढ़ की भगवानी बाई को सामाजिक सुरक्षा का संबल मिला

पं.दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविरों का उद्देश्य यही है – अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक संवेदनशीलता के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ जिले की डूंगला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नाडाखेड़ा निवासी 63 वर्षीय भगवानी बाई की कहानी एक मिसाल बन गई है। भगवानी बाई के परिवार में कोई नहीं है, आय का कोई स्थाई स्त्रोत नहीं, पात्रता होते हुए भी जागरूकता की कमी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव में वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन से वंचित थी। उसे छोटे-छोटे और जरूरी खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए आत्मसम्मान को खटकता भी था। नाडाखेड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में भगवानी बाई ने अपनी व्यथा उपखंड अधिकारी को बताई। उपखण्ड अधिकारी के निर्देश पर मौके पर ही दस्तावेजों का सत्यापन कर भगवानी बाई की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई। अब भगवानी बाई को हर माह पेंशन की राशि नियमित रूप से प्राप्त होगी जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर एक नई शुरुआत कर सकेंगी। उनके चेहरे पर संतोष और आंखों में उम्मीद

की चमक यह सिद्ध करती है कि यह योजना कितनी प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा जी को मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कैम्प में आधे घंटे में मेरा काम करवा दिया। वे इसी तरह जनता की सेवा करते रहें, हम सब का आशीर्वाद और स्नेह उनकी ताकत बने।

■ **उपखण्ड अधिकारी के निर्देश पर मौके पर ही दस्तावेजों का सत्यापन कर भगवानी बाई की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई**

आर्टिकल के संकलन, लेखन और सम्पादनकर्ता चित्तौड़गढ़ सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय में कार्यरत तुलसीराम कंडारा, सुनील पाराशर और आरिफ।

सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों पर राजनीतिकरण

अशोक कुमार

सार्वजनिक क्षेत्र में, बिना राजनीतिकरण के विभिन्न मुद्दों पर विचार ही नहीं किया जाता या हो पाता है। यह एक गहरी जड़ें जमा चुकी प्रवृत्ति है जिसके कई कारण और परिणाम हैं।

सत्ता और प्रभाव की होड़: राजनीति का मूल ही सत्ता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। किसी भी मुद्दे पर चर्चा या निर्णय का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक दल अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाने, विरोधियों को कमजोर करने या अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं।

वोट बैंक की राजनीति: विभिन्न समुदायों, जातियों या वर्गों को लक्षित करने के लिए मुद्दे अक्सर राजनीतिक रंग ले लेते हैं। दल विशेष मुद्दों को इस तरह से उठाते हैं जिससे उन्हें किसी विशिष्ट वोट बैंक का समर्थन मिल सके, भले ही समस्या का वास्तविक समाधान कुछ और हो।

मीडिया का प्रभाव: आज के दौर में मीडिया (खासकर न्यूज़ चैनल) भी अक्सर मुद्दों को सनसनीखेज बनाने और राजनीतिक बहस में बदलने में भूमिका निभाता है। टीआरपी (TRP) और व्यूअरशिप के लिए मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से दिखाना आम बात हो गई है।

विचारधारात्मक ध्रुवीकरण: विभिन्न राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी विचारधाराएं होती हैं। जब कोई मुद्दा सामने आता है, तो उसे अक्सर इन विचारधाराओं के अनुरूप ढाला जाता है, जिससे समस्या के मूल समाधान से हटकर वैचारिक टकराव शुरू हो जाता है।

जवाबदेही से बचना: कई बार राजनीतिकरण का इस्तेमाल किसी समस्या के लिए जवाबदेही से बचने के लिए भी किया जाता है। जब कोई मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन जाता है, तो असली समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है।

प्रचार और दुष्प्रचार: सोशल मीडिया के दौर में, किसी भी मुद्दे को आसानी से राजनीतिक रंग दिया जा सकता है, फिर चाहे वह सही जानकारी के साथ हो या गलत। दुष्प्रचार (misinformation) और फेक न्यूज़ (fake news) का इस्तेमाल भी राजनीतिकरण को बढ़ावा देता है।

इसके परिणाम

समाधान में देरी: जब मुद्दों पर राजनीतिक बहस हावी हो जाती है, तो उनके वास्तविक समाधान पर ध्यान कम हो जाता है या उसमें अनावश्यक देरी होती है।

गंभीरता का अभाव: गंभीर और जटिल मुद्दे अक्सर सतही राजनीतिक बयानबाजी में सिमट कर रह जाते हैं, जिससे उनकी गहराई और गंभीरता कम हो जाती है।

जनता में भ्रम: लगातार राजनीतिकरण से जनता में भ्रम पैदा होता है कि असली समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा। वे अक्सर राजनीतिक दलों के दावों और प्रतिदावों के बीच फंस जाते हैं।

राष्ट्रहित की उपेक्षा: कई बार राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर भी समझौता कर लिया जाता है।

संस्थाओं पर दबाव: राजनीतिक दबाव के कारण कई स्वतंत्र संस्थाएं भी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पातीं, क्योंकि उनके निर्णयों को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है।

क्या बिना राजनीतिकरण संभव है? पूर्ण रूप से बिना राजनीतिकरण के मुद्दों पर विचार करना एक आदर्श स्थिति हो सकती है, लेकिन व्यवहार में यह काफी मुश्किल है। राजनीति लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों का प्रतिनिधित्व करने का माध्यम है, और स्वाभाविक रूप से कोई भी मुद्दा जो समाज को प्रभावित करता है, वह राजनीतिक दलों के लिए प्रासंगिक हो जाता है।

हालांकि, महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिकरण इस हद तक न बढ़ जाए कि वह समाधान और विकास के रास्ते में बाधा बने। एक स्वस्थ लोकतंत्र में, राजनीतिक बहस होनी चाहिए, लेकिन यह बहस तथ्यों और समाधान पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल आरोप-प्रत्यारोप या वोट बैंक की राजनीति पर। सार्वजनिक विचार-विमर्श में अधिक परिपक्वता, मीडिया की अधिक जिम्मेदारी और राजनीतिक दलों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की भावना ही इस प्रवृत्ति को कम करने में मदद कर सकती है।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

चातुर्मास आत्मशुद्धि, संयम और सामाजिक सद्भाव का विशेष काल है : राज्यपाल बागड़े

राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े ने भीलवाड़ा में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की

कभीलवाड़ा, (निसं)। राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े ने कहा कि चातुर्मास आत्मशुद्धि, संयम और सामाजिक सद्भाव का विशेष काल है, जिसमें साधु-संत एक स्थान पर ठहरकर साधना, ध्यान और तपस्या करते हैं तथा समाज को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े ने मंगलवार को आध्यात्मिक चातुर्मास महोत्सव समिति भीलवाड़ा के तत्वावधान में सुभाष नगर स्थित जैन स्थानक में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम संबोधित किया।

राज्यपाल ने कहा कि जैन धर्म जीवदया, अहिंसा और आत्मशुद्धि का प्रतीक है तथा चातुर्मास के माध्यम से इन मूल्यों को जनमानस तक पहुँचाया जाता है। उन्होंने कहा कि सच्चा साधु वही है जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है और दूसरों के हित में किया गया कार्य ही सच्ची सिद्धि है। यह परंपरा भगवान महावीर के काल से चली आ रही है, जिसका उद्देश्य समाज में नैतिक जागरूकता और

राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े ने भीलवाड़ा में सुभाष नगर स्थित जैन स्थानक में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।

आध्यात्मिक चेतना जागृत करना है। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि चातुर्मास के दौरान दिए जाने वाले प्रवचन व्यक्ति के अंतर्मन को जागृत करते हैं और समाज में सकारात्मक सोच का संचार करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को मिटाने के अनेक प्रयास इतिहास में हुए, लेकिन इसकी गहराई और मूल्यों के कारण यह संस्कृति आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने नवीन शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नीति बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ-साथ उनके नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन पर बल देती है। उन्होंने कहा कि नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से ऐसे शिक्षाविद् तैयार होंगे, जो आधुनिक ज्ञान के साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत को भी आत्मसात करेंगे। राज्यपाल बागड़े ने मंच पर विराजित जैन साध्वियों से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके द्वारा समाज को दिए जा रहे आध्यात्मिक मार्गदर्शन की सराहना की। राज्यपाल के दौरे के दौरान कार्यक्रम स्थल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा समुचित तैयारियां की गई थी। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन एवं अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे, जिससे कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, आसींद विधायक जब्बर सिंह सांखला, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या , महापौर राकेश पाठक, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

■ **राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े ने मंच पर विराजित जैन साध्वियों से आशीर्वाद प्राप्त किया**

आजादी के बाद देवपुरा मार्ग को कानूनी मान्यता मिली

अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ने ग्राम देवपुरा के लोगों को राहत दी

नसीराबाद, (निसं)। नसीराबाद उपखंड की ग्राम पंचायत राजगढ़ में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ने ग्राम देवपुरा के लोगों के लिए ऐतिहासिक राहत का काम किया। शिविर में वर्षों से लंबित मांग को पूरा करते हुए गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला रास्ता पहली बार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।

जानकारी के अनुसार देवपुरा, जो गुर्जर बाहुल्य इलाका है, में आज़ादी के बाद से आबादी तक जाने वाला मुख्य मार्ग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। इससे किसानों को कृषि भूमि के उपयोग और तकनीकी कार्यों में लगातार दिक्कत आ रही थी। शिविर में ग्रामीणों ने इस गंभीर समस्या को उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव और तहसीलदार ममता यादव के सामने रखा।

शिविर के दौरान अधिकारियों ने मौके पर राजस्व टीम के साथ स्थिति का जायजा लिया और तुरंत ही रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश के साथ ही ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो गया और उन्हें बड़ी राहत मिली। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत राजगढ़ ने उपखंड प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम का आभार जताया। उनका कहना है कि इस फैसले से भविष्य में विकास कार्यों और सुविधाओं के विस्तार में भी मदद मिलेगी।

राशिफल

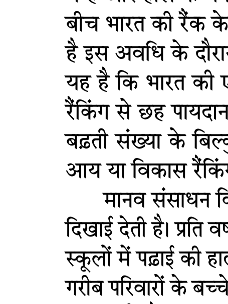

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 9 जुलाई, 2025

आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, चतुरदशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, मूल नक्षत्र रात्रि 4:50 तक, ब्रह्म योग रात्रि 10:9 तक, गर करण दिन 1:08 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-धनु, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग सूर्योदय से रात्रि 4:50 तक है। रवियोग रात्रि 4:50 तक रहेगा। राजयोग रात्रि 4:50 से सूर्योदय तक है। आज भद्रा रात्रि 1:37 से आरम्भ होगा। आज चौमासी चौदस (जैन), शिवशयन चतुरदशी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:08 तक, शुभ 10:50 से 12:32 तक, चर 3:56 से 5:38 तक, लाभ 5:38 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:43, सूर्यास्त 7:20

मेष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियों से राहत मिल सकती है। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।